आकाशवाणी
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 10.01.2026 समय 1305

मुख्य समाचार :–

- संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी बांध विस्थापितों को शीघ्र राहत देने का आश्वासन दिया।
- चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की।
- ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा में सात दिवसीय उत्तरायणी कौतिक शुरू।

संसद बजट सत्र

संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख़ से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। श्री रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है।

टिहरी बांध विस्थापित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लम्बे समय से भूमिधरी अधिकार की मांग कर रहे टिहरी बांध विस्थापितों को आश्वस्त किया कि इस मामले में और विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और उनके अधिकारों का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री आवास में टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र संघर्ष समिति पथरी, हरिद्वार और ग्राम पंचायत आदर्श टिहरी नगर, बहादराबाद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने भूमिधरी अधिकार और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। श्री धमी ने मौके पर हरिद्वार और टिहरी के जिलाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की और वैधानिक व प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि विस्थापित परिवारों को शीघ्र राहत मिल सके।

वीबी जी राम जी

सांसद अजय भट्ट ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण– वीबी जी राम जी योजना को ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और लोक कल्याण की दिशा में मील का पत्थर बताया है। वे हल्द्वानी में वीबी राम जी पर पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, मजदूरों के लिए समर्पित व प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। श्री भट्ट ने कहा कि वीबी जी–राम–जी योजना के नाम पर कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय में वृद्धि होगी।

कूड़ा डंपिंग जोन

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगर निगम क्षेत्र, बीएचईएल टाउनशिप, सिडकुल, शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि जिले को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए एक माह 21 दिन से लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बीएचईएल के अधिकारियों से अपेक्षा की है कि बीएचईएल टाउनशिप, सिडकुल और शिवालिक नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत सफाई व्यवस्था में पूरा सहयोग दें। साथ ही बीएचईएल क्षेत्र के तहत जिन स्थानों में कूड़ा कचरा डंप किया गया है, उन स्थानों को साफ करने और अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा फेंकने वालों के चालान करने के लिए भी निर्देशित किया।

भापथ

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उन्हें दोपहर करीब दो बजे देहरादून स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 8 जनवरी को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई थी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।

बैठक

चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने इस साल होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने पेयजल, बिजली, यातायात, पैदल मार्ग, हेलीपैड निर्माण और यात्री सुविधाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वीकृत कार्यों पर शीघ्र निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने देवाल–वांण मार्ग पर वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने, वांण सड़क पर चल रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर आवश्यक सुधार करने और प्रस्तावित हेलीपैड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग पर पेयजल व्यवस्था को समय पर

पूरा करने के लिए जल संस्थान और वन विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया। साथ ही निर्जन पड़ावों पर पड़ाव अधिकारियों की नियुक्ति और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बेदनी सहित अन्य निर्जन पड़ावों पर सोलर प्लांट लगाने की संभावनाओं पर योजना तैयार करने को कहा गया। बैठक में यात्रा के दौरान वाहन पार्किंग की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। वांण, लाटू धाम, नंदकेसरी और अन्य पड़ावों के समीप वैकल्पिक पार्किंग के लिए भूमि चयन के निर्देश दिए गए। पर्यटन विभाग को निर्जन पड़ावों पर आवास व्यवस्था को लेकर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा गया।

उत्तरायणी कौतिक

ऊधम सिंह नगर जिले के तराई बीज विकास निगम मैदान, खटीमा में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के तत्वावधान में सात दिवसीय उत्तरायणी कौतिक शुरू हो गया है। उत्तरायणी कौतिक में कुमाउंनी और गढ़वाली संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति किए जा रहे हैं, वहीं लोक गायकों की सजीव प्रस्तुतियों पर ढोल दमाऊं, हुड़का और रणसिंगा की थाप ने माहौल को जीवंत बना दिया है। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोक संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम की सांस्कृतिक प्रभारी सावित्री चंद ने बताया कि हमारे बच्चे अपनी बोली भाषा और संस्कृति को भूलते जा रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति जागरुक करना है।

अतिक्रमण

हल्द्वानी शहर के प्रमुख बाजारों में लगातार बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बार–बार चेतावनी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बावजूद व्यापारियों द्वारा सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा किए जाने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने मीरा मार्ग सहित सदर बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर दुकान का सामान फैलाकर आवागमन बाधित कर रहे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त किया गया।

जीएसटी संग्रह

राज्य कर विभाग के हल्द्वानी सम्भाग में वस्तु और सेवा कर– जीएसटी संग्रह दिसम्बर माह में 31 करोड़ 90 लाख रूपये रहा। हल्द्वानी सम्भाग के संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, राज्य कर, रोशन लाल ने बताया कि जीएसटी संग्रह में कुल 23 हजार 928 पंजीकृत डीलरों वाले नैनीताल जिले ने सर्वाधिक 24 करोड़ 78 लाख रूपये का योगदान किया है। वहीं वर्ष 2024 के दिसम्बर माह की तुलना में सबसे कम पंजीकृत डीलरों वाले बागेश्वर जिले से इस बार 27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 91 लाख रूपये का जीएसटी संग्रह हुआ है।